

**पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश
नागरिक चार्टर**

(वेबसाइट <http://backwardwelfare.up.nic.in>)



वर्ष 2015-2016

**पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन**

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय



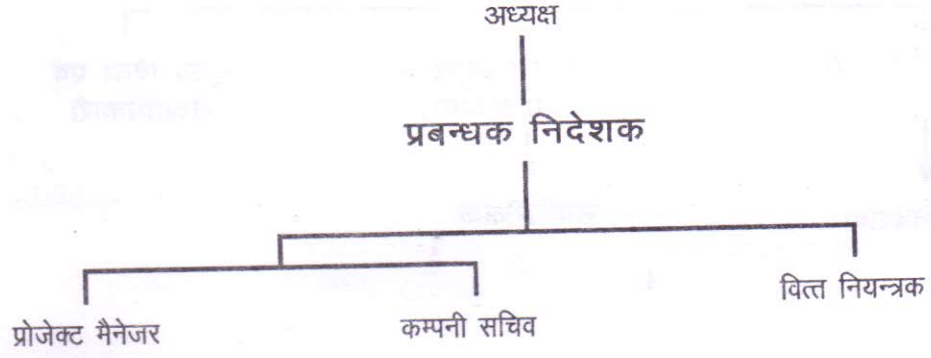
जोनल स्तर पर

उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण

जनपद स्तर पर

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि० का संगठनात्मक ढाँचा



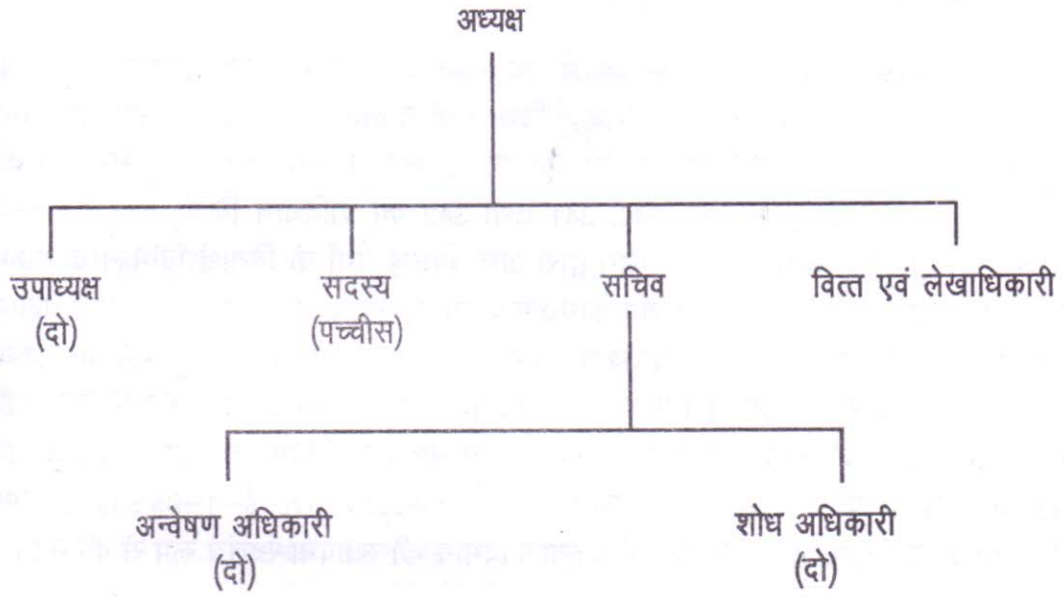
जोनल स्तर पर

उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण पदेन मण्डलीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम लिमिटेड

जनपद स्तर पर

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संगठनात्मक ढाँचा



पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

धर्म निरपेक्षता और प्रजातांत्रिक प्रणाली को आधार मानकर भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को जहाँ समानता का अधिकार दिया गया है वहीं समाज के कमजोर और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से ऊँचा उठाने हेतु संविधान की धारा 14, 15, 16, 335, 338, 339, 340, 341 तथा 342 का प्राविधान किया गया है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 1995-96 तक यह कार्यक्रम प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की 54.05 प्रतिशत (सामाजिक न्याय समिति के अनुसार) जनसंख्या पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित है और इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास एवं कल्याण हेतु निःसन्देह ही एक स्वतंत्र विभाग की आवश्यकता का अनुभव बहुत पहले से किया जा रहा था। अतः वर्ष 1995-96 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या 4056/बीस-ई-1-95/539 (2)/95 दिनांक 12 अगस्त 1995 द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से की गई।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उ०प्र० पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि० तथा उ०प्र० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संचालित है।

उ०प्र० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शासनादेश संख्या- 22/16/92-कार्मिक-2 दिनांक 09 मार्च 1993 में किया गया था जो राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण, पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित जातियों का समावेश करने अथवा निष्कासित करने का कार्य कर रहा है।

उ०प्र० पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि० की स्थापना शासनादेश संख्या-3459/26-03-89-9(51)89, दिनांक 20 सितम्बर 1989 द्वारा की गयी है, जो पिछड़े वर्ग के कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उ०प्र० की स्थापना शासनादेश संख्या-1826/26-2-95 दिनांक 20 सितम्बर 1995 द्वारा की गयी है तथा निदेशालय, मण्डल एवं जिला स्तर पर राजपत्रित/अराजपत्रित पदों का सृजन कर कार्यालय संचालित है। संगठनात्मक ढांचा पृष्ठ-1, 2 व 3 पर उपलब्ध है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम एक दृष्टि में

(1) पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा संचालित योजनायें

क्रं. सं.	योजना का नाम	पात्रता	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिमाह)			अर्हता / प्रक्रिया
			कक्षा	दिवा छात्र	आवासीय छात्र	
1	2	3	4	5	6	7
	पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति योजना					वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु यह योजना स्थगित रखी गयी है।
	1. पूर्वदशम छात्रवृत्ति					
	(अ) कक्षा 1 से 8	पिछड़े वर्ग के सभी छात्र/ छात्राओं को	1. कक्षा 1-5 तक रु. 25/- मासिक			
			2 कक्षा 6-8 तक रु. 40/- मासिक			

